



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1944 (श10)
(सं0 पटना 961) पटना, वृहस्पतिवार, 10 नवम्बर 2022

सं० 3/एफ-01-24/2008-10443/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

9 नवम्बर 2022

विषय:—सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता के भुगतान के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-6530, दिनांक-31.07.2008 की कंडिका-2 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान 18,400-500-22,400 रुपये एवं इससे ऊपर के वेतनमान में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को (चाहे वो किसी भी सेवा के हों) घरेलू सहायता भत्ता के लिए 3000/-रुपये प्रति माह उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमान्य है, उन्हें दोनों में से एक सुविधा चुनने का विकल्प है। दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण के उपरान्त इस व्यवहारिक सुविधा का निर्धारण वर्ष 2008 में किया गया।

2. राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण दिनांक-01.01.2006 एवं दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से क्रमशः 1.86 एवं 2.57 फिटमेंट गुणक के आधार पर किया गया है। जबकि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों एवं निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए घरेलू सहायता भत्ता का पुनरीक्षण/पुनर्निर्धारण नहीं हो सका है।

3. श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना सं०-3809, दिनांक-30.09.2022 द्वारा अकुशल मजदूर हेतु दिनांक-01.10.2022 के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी 373.00 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा वेतन-स्तर-14 एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता को निम्नरूप से पुनरीक्षित किया जाता है :-

(i) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में वेतन-स्तर-14 एवं इससे ऊपर के वेतन-स्तर में पदस्थापित पदाधिकारियों को (चाहे वे किसी भी सेवा के हों) घरेलू सहायता भत्ता के रूप में 11,190/- (ग्यारह हजार एक सौ नब्बे रुपये) (373रु०X30दिन) प्रतिमाह भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर में पुनरीक्षण किये जाने की स्थिति में घरेलू सहायता भत्ता भी उस हद तक पुनरीक्षित हो जायेगा।

(ii) आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अंतर्गत अनुमान्य है, दोनों में से एक विकल्प चुन लेंगे।

(iii) वित्त विभागीय संकल्प सं०-6530, दिनांक-31.07.2008 में मात्र इस राशि संशोधन के अलावे शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे। यह सुविधा नवम्बर 2022 माह से प्रभावी होगी तथा इस सुविधा पर होने वाले व्यय, संबंधित विभाग के वेतन मद से विकलित होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव संसाधन।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 961-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**